very efficient; his administration is good. I appreciate that. I want to know from the hon. Minister whether he has done some audit to know about the backlog, whether the CAT Scan Machines are working or not, how many doctors are suggesting to patients to go and get their MRI reports done and whether it is done in the premises of the AIIMS or it is done in Green Park or at some other places. Have you done any enquiry about it or not? If you have not done it, by what time you will get it done?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, I have already stated that it is a continuous process. We have different Committees to go through it. At the end of it, we have the Institute's Governing body. Within that, we have the finance body, the academic body, etc. So, all Committees are there. They have to have periodic discussions and meetings, and go through the audit, whether it is the financial audit or patient audit or safety audit. All these audits are being done periodically and then being laid on the floor of the Parliament as well. But, unfortunately, Sir, we all know that what sort of scenario the AIIMS was in, in the last few years. I don't want to dwell more on that. But, we are trying to rectify the situation now. It has been going through a bad patch, I accept and acknowledge that. And as a Government, we were having problems with the administration at that point of time. Now, it is all gone behind. Now, we are trying to move forward; it is going to take some time, though. But, that has nothing to do with all these audits. I would like to welcome the suggestions of the hon. Member and the other hon. Members also. If they have any other complaint or any other module of better management, please bring it to our notice, and we will, definitely, put it into the best practices of the administration of the AIIMS. But, I would like to assure this House that things are going on a good track in the AIIMS today, and all these audits are imbibed into the structure of the AIIMS itself. There may be one or two lapses here and there, which happens in all the institutions; and to prevent those lapses also, we are trying our best to plug in the loopholes.

Exemption of export duty

*162. SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: ††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether his Ministry has asked Government to consider exemption of export duty on certain products like cold rolled coils, for which raw materials have been imported under the Advance Licensing Scheme (ALS);

(b) if so, whether despite export duties announced on various steel products, it would be prudent for Government to consider allowing duty-free export of CR coils, galvanized steel, tubes and pipes, for which HR coils have been imported under ALS;

(c) whether Government has considered roll back of export duty; and

(d) if so, by when final decision in this regard is likely to be taken?

THE MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gireesh Kumar Sanghi

Statement

(a) During the month of April 2008, Ministry of Steel had taken up the issue with Ministry of Finance for devising a scheme for exemption of export duty on exports of such steel products, the input material of which was being imported under the Advance Authorisation Scheme (AAS) for further value addition and exports. This scheme was conceived to achieve two objectives;

(i) To discourage export of domestic steel from being exported out of country after further processing and value addition and thereby improve domestic steel availability.

(ii) To facilitate manufacturers with surplus capacity to export value added steel products only against import of the corresponding quality materials.

(b) Export duty on hot rolled (HR) coil, cold rolled (CR) coil, pipes and tubes etc. was withdrawn *with effect from* 13.06.2008. Therefore the scheme was not implemented.

(c) and (d) The Government has rolled back export duty on all categories of steel items, except melting scrap, *w.e.f.* 31.10.2008.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, the reply of the hon. Minister states that the Government has rolled back export duty on all categories of steel items, except melting scrap, *w.e.f.* 31.10.2008. Sir, my supplementary to the hon. Minister is whether the Government is thinking in terms of roll back in the import duty on steel and how would the Government encourage export of steel from India in the given scenario. Sir, in the given scenario, the steel market is going down and consumptions are also falling down within the country. Sir, there are countries like China whose consumptions are much less than production. China consumes about 482 million tonnes of steel, and produces 537 million tonnes. So, in China, there is a gap of almost 100 million tonnes in the consumption and production of steel. It produces about 100 million tonnes of extra steel. So, there is likelihood that China would dump steel into our country because we are its neighbouring country. So, what is the plan of the Government of India in this area?

श्री राम विलास पासवान: सर, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज से बात की है, सारी इंडस्ट्रीज से, जिसमें consumer associations के भी लोग हैं और यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण स्टील के दाम काफी गिर गए हैं और मेरे पास फिगर्स भी हैं। जून, 2008 में जहां 50,000 रुपए HR Coil का दाम था, वह दिसम्बर, 2008 में घटकर 41,000 रुपए हो गया है। TMT जहां जून, 2008 में 47,000 रुपए था, अब 33,000 हो गया है। Pig Iron भी 39,000 रुपए से घटकर 26,000 के करीब हो गया है। दूसरी बात, जो consumption है, consumption का रेट एक समय 13 परसैंट था, जो अब घटकर करीब दो, पौने दो परसैंट पर आ गया है। यह सिनेरिओ है, हालांकि हमें इस बात की खुशी है कि दूसरे राष्ट्रों पर मंदी का जितना असर पड़ा है, हमारे यहां के स्टील उद्योग पर मंदी का उतना असर नहीं पड़ा है। यदि आप बाद के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो मैनपावर की कटौती का सवाल है, उसमें हमें जो रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार अभी तक मैनपावर की कटौती नहीं की गई है, लेकिन यह प्रभाव पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज से इस बारे में हमारी बातचीत हुई है, इंडस्ट्रीज ने जो-जो कहा, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के लिए कहा, हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में कहा, 5 परसेंट से ज्यादा की मांग थी, हमने उस पर 5 परसेंट लागू करने का काम किया, CVD वगैरह। इस तरह ये सारे measures अपनाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट का जो नया

पैकेज निकला है, उसमें भी इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंडस्ट्रीज हैं, उनको ज्यादा घाटा न हो, उनको किसी न किसी तरीके से sustain किया जाए और इसके बारे में सरकार चिंतित है।

श्री गिरीश कुमार सांगी: सभापति जी, मंदी और तेजी तो cyclic होती है। अभी हम मंदी में हैं और अब तेजी आना अवश्यंभावी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तेजी लाने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। आज अगर हम देश में स्टील के उत्पादन का आंकड़ा देखें, तो we are producing about 60 million tonnes of steel, in comparison to 600 million tonnes of steel in China. हमारे देश में अगर कोई भी आदमी एक स्टील मिल लगाना चाहता है, तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि अखबारों में रोज इसके बारे में आता रहता है। हमारे पास जो iron ore है, उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां के जो उत्पादक हैं, उनको न तो iron ore मिलता है, न coal मिलता है। इस मामले में मंत्री जी क्या कर रहे हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, जिस समय UPA की सरकार आई थी और मैंने मंत्री पद ग्रहण किया था, उस समय स्टील के उत्पादक देशों में हमारा स्थान 8वां था, जो अब 5वां हो गया है। उस समय हमारे यहां 35 मिलियन टन का उत्पादन होता था, अब हमारा उत्पादन बढ़कर 54 मिलियन टन हो गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो प्रभाव है, वह प्रभाव पड़ता है। हमने अपनी नेशनल पालिसी बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि 2020 तक हमारे यहां 124 मिलियन टन का उत्पादन होगा, उसको अब हमने रिवाइज करके कहा कि 2011-2012 तक हम 124 मिलियन टन का उत्पादन करेंगे और 2020 तक हम करीब 280 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखेंगे। हमारे यहां दो तरह के फील्ड हैं, उनसे से एक brown field है, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां सारा infrastucture available है, लेकिन जहां तक green field का सवाल है, उसमें हमें राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है और उसमें जरूर कठिनाई होती है। जहां तक iron ore का सवाल है, वैसे Ministry of Mines के अनुसार हमारे यहां iron ore 29 बिलियन टन है, लेकिन जो high quality का है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री का हमेशा से ही यह विचार रहा है कि जो high quality का iron ore है, उसके एक्सपोर्ट पर या तो रोक लगानी चाहिए या उसके एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि जो Mines Department है, उसके अंतर्गत भी employees काम करते हैं, mines industries में करीब 50 लाख employees हैं, उनको भी हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को लागू किया गया है। हम माननीय सदस्य की इस राय से सहमत है कि जो हमारी domestic needs हैं, उनको देखते हुए ही भविष्य की पॉलिसी बननी चाहिए और उसी के अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं।

SHRI N.K. SINGH: Sir, we all know that export duties are fiscal tool in the hands of Government for managing demand-supply equilibrium and to mitigate any inflationary impact. Looking at the past experience, does the Ministry have any credible mechanism for monitoring the long-term behavioural patterns of demand-supply management of steel globally?

श्री राम विलास पासवान: सर, जैसा कि मैंने कहा कि डिमाण्ड और सप्लाई वर्तमान situation पर निर्भर करती है। हम इस बात को भी मानते हैं कि अभी जो मंदी का दौर आया है, यह मंदी का दौर खास करके स्टील इंडस्ट्री में परमानेंट रहने वाला नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक समय में जहां कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारा consumption rate 13 परसेंट था, आज वह घटकर पौने दो परसेंट पर चला आया है, लेकिन हम निश्चित रूप से डिमाण्ड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाते हैं। अभी माननीय सदस्य द्वारा price stability के लिए

प्रश्न पूछा गया था, उसमें हम लोगों ने जो अभी तक कारगर कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं - इस्पात उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी पांच परसेंट से घटा करके जीरो परसेंट कर दी गई है, सरिया पर सीवीटी चौदह परसेंट से nil कर दी गई है, दिनांक 10.05.2008 से इस्पात उत्पाद पर export duty पांच परसेंट से 15 परसेंट कर दी गई है, दिनांक 13.06.2008 से फ्लेक्स प्रोडक्ट पर export duty हटा ली गई है, Iron ore पर export duty 15 परसेंट लगा दी गई है, 30.10.2008 से सभी उत्पादों पर export duty हटा ली गई है, जिसका प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, दिनांक 14.111.2008 को DBPG benefit restore कर दी गई है, दिनांक 14.11.2008 को पांच परसेंट import duty दोबारा लगा दी गई है और दिनांक 17.11.2008 को excise duty 14 परसेंट से घटा कर के 10 परसेंट कर दी गई है और iron ore पर से सभी export duty हटा ली गई है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Hon. Chairman, Sir, through you, I want to put a specific question to the Minister. Now there are many forecasts about whether the recession is going to be temporary or long, but one thing is clear that the recession in the global advanced industrial economy is going to be severe at least in the coming the next six, seven or eight months resulting in a bright prospect of dumping of steel being produced outside in the Indian market. I would like to know whether the Steel Ministry in view of that thing is aware of this fact that in our country there is an ample scope of demand for steel, but possibility of dumping in view of the recession in the manufacturing abroad may have a very negative impact in the form of dumping and disturbing our domestic steel facilities. I would like to know further whether the Ministry is having- I do not say long-term, but, at least a medium-term - any approach of curbing that kind of prospect of dumping on Indian soil which may affect adversely the Indian domestic steel industry.

श्री राम विलास पासवान: सर, जैसा कि मैंने कहा कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो export duty पर छूट देना और दूसरा import duty लगाना। Import duty already लगाई जा चुकी है, जिससे बाहर से जो माल आता है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाए, लेकिन इसके बावजूद दाम में जो इतनी कमी आ रही है, उस कमी को देखते हुए यह थोड़ा कठिन है। लेकिन वित्त मंत्रालय है, चूंकि हमारे यहां दो तरह के हैं, एक secondary association है और दूसरे producers भी हैं, इन दोनों के हित को देखते हुए ही सरकार निर्णय लेती है।

AIIMS like institutions in the north-east

*163. SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is planning to include North East Region (NER) in its mission of setting up AIIMS like institutions;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, reasons therefor, in so far as AIIMS like institutions will solve the problems of entire NER?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences (NEIGRIHMS) has been established in Shillong, on the lines of AIIMS, New Delhi, and PGIMER, Chandigarh, with the objective of providing advanced specialized Health-Care to the people of North-East Region. So far